

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 41/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/47)

ग्राम पंचायत कोहला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोहला पंचायत
समिति हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।
2. ग्राम पंचायत रामसरानारायण जरिये सरपंच ग्राम पंचायत
रामसरानारायण पंचायत समिति हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

- उपस्थित:
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. श्री विनोद कुमार पुरोहित | — अभिभाषक अपीलान्ट |
| 2. श्री कौशल आचार्य | — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 2 |
| 3. श्री महेश स्वामी | |
| 4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली | — राजकीय अभिभाषक |

निर्णय

दिनांक: 16.10.2023

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत
अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 27.06.2022 के
विरुद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार (राजस्व)
हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश क्रमांक टीआरए/आबादी/21/ 109
दिनांक 25.11.2021 द्वारा चक 19 एचएमएच की कृषि भूमि को ग्राम
पंचायत रामसरानारायण के नाम से हस्तांतरित करने, तथा उक्त
भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत कोहला गैरखातेदार के
स्थान पर ग्राम पंचायत रामसरानारायण गैरखातेदार के नाम
नामान्तरण दर्ज कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु पटवारी हल्का
रामसरानारायण को आदेश दिया। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ
के आदेश दिनांक 25.11.2021 के विरुद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील
अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ में पेश कर उसे निरस्त करने तथा
उसके आधार पर दर्ज नामान्तरण सं. 732 दिनांक 25.11.2021 को
निरस्त कर अपील में दर्ज विवादित कृषि अपीलान्ट के नाम से दर्ज
किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अपर जिला कलेक्टर
हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.06.2022 द्वारा अपीलान्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर



आदेश विधि सम्मत होने का मानकर अपीलान्त की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश कर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2022 व तहसीलदार हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 25.11.2021, दोनों आदेशों को निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार करने का निवेदन किया।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. इस न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 25.07.2022 के विरुद्ध अपीलान्त ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की, माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 27.09.2022 को निगरानी खारिज कर उभय पक्ष को सुनकर विधि अनुसार अपील का निस्तारण करने का इस न्यायालय को निर्देशित किया।
5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्त ग्राम पंचायत कोहला है जो कि राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत कार्य करता है। यह कि विवादित कृषि भूमि चक 19 एचएमएच के खाता सं. 150 पं. नं. 129/284 (49) किला नं. 11 ता 14, 17 ता 19, 23 ता 25 कुल 2.530 हैक्टर नहरी 0.506 हैक्टर कमाण्ड 2.024 अनकमाण्ड अलॉटमेंट में राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के नाम से दर्ज है जो कि अपीलान्त के क्षेत्राधिकार की कृषि भूमि है। ग्राम कोहला पंचायतीराज के स्थापना से ग्राम पंचायत के रूप में चली आ रही है जबकि रेस्पोंडेन्ट सं. 2 को सन् 1985 में पंचायतों के पुर्नगठन में ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा से अलग कर स्थापित किया गया था। स्पष्ट है कि रेस्पोंडेन्ट सं. 2 कभी भी अपीलान्त को पंचायत क्षेत्र का भाग नहीं रही है। विवादित कृषि भूमि की अलॉटी अपीलान्त ग्राम पंचायत कोहला है जिसे 10 बीघा दिनांक 29.02.1968 को आवंटन की गई, आवंटन के बाद अपीलान्त के नाम इंतकाल सं. 5 दिनांक 20.12.1968 राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया। उक्त भूमि पूर्व में जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 28.06.2001 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये थे उक्त


जतिरिक्त संभागीय आयुक्त
सीतामढ़ी



निर्णय के विरुद्ध श्रीमान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, उक्त प्रकरण में दिनांक 09.09.2023 को श्रीमान द्वारा निर्णय किया गया जिसके मुताबिक अपीलान्त की अपील स्वीकार की गई एवं कलक्टर हनुमानगढ़ के आदेश 28.06.2001 को निरस्त किया गया। आदेश दिनांक 09.09.2023 अंतिम आदेश था उसकी कोई अपील पेश नहीं की गई। इस पूरी कहानी को छुपाकर अपील पेश की गई है। उक्त प्रकरण रस-ज्यूडिकेट के सिद्धान्त से बाधित रहे थे। इस बिन्दु पर नजीरात निम्न है। आर.एल. डब्ल्यू 2010 (1) आर जे पेज 114, आर.आर. डी 1988 पेज 443, ए.आई.आर 2007 एम.पी पेज 112 है। साथ ही उक्त भूमि को हड़डारोडी हेतु दिया गया है। आलॉटमेंट से प्राप्त भूमि का नामान्तरण बिना सहमति के किसी अन्य के दर्ज नहीं किया जा सकता है। जबकि रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा ऐसी कोई सहमति अपीलान्त से नहीं ली गई। अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आदेश व नामान्तरण दर्ज किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 25.11.2021 को पारित करने के लिए मुख्य आधार कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ के प्रस्ताव को आधार बनाकर आदेश पारित किया जो प्रस्ताव इनके द्वारा अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी करते हुए बिना किसी आधार रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश में किसी भी दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया है। अतः अपीलान्त द्वारा दिनांक 05.09.2023 के प्रार्थना पत्र साथ सलग्न दस्तावेज को पत्रावली में शामिल कर अपील अपीलान्त स्वीकार कर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 27.06.2022 व तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 25.11.2021 जिसके तहत जारी नामान्तरण सं. 732 दिनांक 25.11.2021 को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

- रेस्पोंडेंट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि तहसीलदार ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 102 क में दिये गये अधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है जो



विधि सम्मत है। पुरानी ग्राम पंचायत कोहला टूटने के बाद ग्राम पंचायत रामसरा नारायण बनने के बाद कुछ राजस्व चक ग्राम पंचायत रामसरा नारायण में आ गये। अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया अपनाकर की गई है। अपीलान्त का उक्त भूमि पर ना तो कोई कब्जा है व ना ही किसी तरह से उपयोग करने का अधिकार है। वर्तमान में उक्त भूमि हड़ारोडी हेतु ठेका दे रखा है। अपीलान्त को इस स्टेज पर दस्तावेज पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। बेवजह न्यायालय के अमूल्य समय को जाया करने हेतु एवं प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, जबकि उक्त समस्त दस्तावेज यदि अपीलान्त के हित में हैं तो अधीनस्थ न्यायालय में ही पेश किए जाने चाहिए थे। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं लिया जावे तथा अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।

7. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 सही है अतः अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।
8. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रकरण के विवेचन व विश्लेषणपरान्त पाया कि पटवारी हल्का रामसरानारायण की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2021 अनुसार चक 19 एच.एम.एच पटवार मंडल रामसरानारायण में स्थित है। जबकि चक 19 एच.एम.एच के खाता सं. 150 मे प. नं. 129/284 मु. नं. 49 किला नं. 11 ता 14, 17 ता 19, 23 ता 25 कुल किता 10 रकबा 2.530 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत कोहला गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पटवार मंडल रामसरानारायण में स्थित है। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत दिनांक 25.11.2021 को उक्त भूमि वर्तमान में पूर्व में सृजित ग्राम पंचायत रामसरानारायण के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने के कारण राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत कोहला गैर खातेदार के स्थान पर ग्राम पंचायत रामसरानारायण गैर खातेदार के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए गए। तदनुसार उक्त भूमि का ग्राम पंचायत रामसरानारायण के



खाते अमल दरामद किया गया। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के प्रस्ताव व सरपंच ग्राम पंचायत रामसरानारायण के अनापत्ति हलफनामा के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 16.03.2022 उक्त भूमि में सें 1.442 हैक्टेयर भूमि नगर परिषद हनुमानगढ को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित करने का आदेश प्रदान किया गया, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही सुसंगत विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में की जानी प्रतीत होती है, अतः उक्त विवेचन विश्लेषण के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 29/2021 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 में हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 29/2021 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

9. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर